गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 033
दि. 02.06.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

शुभेंदु सरकार का पहला शक्ति प्रदर्शन, 35 नए मंत्रियों के साथ बंगाल कैबिनेट का बड़ा विस्तार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार का दिन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का गवाह बना। एक ओर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सत्ता संभालने के बाद पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने दो विधायकों को निष्कासित कर सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। इन दोनों घटनाओं ने राज्य की राजनीति को एक साथ नई दिशा और नया संदेश देने का काम किया है।

लोकभवन में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आर.एन. रवि ने 35 नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विस्तार केवल मंत्रिमंडल का आकार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आगामी वर्षों के प्रशासनिक एजेंडे और राजनीतिक संतुलन को साधने की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी है।

294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मंत्रियों की अधिकतम संख्या 44 हो सकती है। ऐसे में सरकार ने अभी भी तीन पद रिक्त रखे हैं, जिससे भविष्य में राजनीतिक परिस्थितियों और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार नए चेहरों को शामिल करने की संभावना बनी हुई है।

मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा नेतृत्व ने अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास

किया है। स्वपन दासगुप्ता, दुध कुमार मंडल, दीपक बर्मन, मनोज उरांव, गौरी शंकर घोष, अर्जुन सिंह, तपस रॉय, शरद्वत मुखर्जी, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और शंकर घोष सहित कई वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं राजेश महाता, इंद्रनील खान और मालती रावा रॉय को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में स्थान मिला है।

सूत्रों के अनुसार विभागों के बंटवारे को लेकर भी सरकार के भीतर गहन विचार-विमर्श जारी है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में विभागों का आवंटन कर प्रशासनिक कामकाज को और गति दी जाएगी। सरकार की प्राथमिकता उद्योग, रोजगार, कृषि, शहरी विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े विभागों को मजबूत करने की बताई जा रही है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस विस्तार के माध्यम से भाजपा ने राज्य के विभिन्न सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। विशेष रूप से उत्तर बंगाल, जंगलमहल और सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले नेताओं को शामिल कर पार्टी ने क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है। साथ ही पहली बार विधायक बने कुछ नेताओं को भी अवसर देकर भाजपा ने युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है।

इसी बीच राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी बड़ा संगठनात्मक कदम उठाते हुए अपने दो विधायकों संदीपान साहा और ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी ने दोनों नेताओं पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई को टीएमसी नेतृत्व द्वारा संगठन में अनुशासन कायम रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

दोनों विधायकों पर कार्रवाई ऐसे समय हुई जब विधानसभा के भीतर विपक्ष के नेता के चयन और कथित फर्जी हस्ताक्षर विवाद को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में आयोजित एक मीडिया वार्ता के दौरान इस विवाद का उल्लेख किया था। इसके कुछ ही समय बाद तृणमूल कांग्रेस ने दोनों विधायकों के निष्कासन की घोषणा कर दी।

पार्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दोनों विधायक बार-बार संगठनात्मक बैठकों से अनुपस्थित रहे और ऐसे बयानों एवं गतिविधियों में शामिल पाए गए जिनसे पार्टी की छवि और हितों को नुकसान पहुंचा। टीएमसी की उपाध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में स्पष्ट किया गया कि पार्टी विरोधी आचरण को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसी कारण दोनों नेताओं की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा रही है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एक ही दिन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार और विपक्षी दल में अनुशासनात्मक कार्रवाई ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जहां भाजपा सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और शासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस संगठन के भीतर अनुशासन और एकजुटता बनाए रखने की चुनौती से जूझती नजर आ रही है।

आने वाले दिनों में मंत्रियों को विभागों का आवंटन, सरकार की प्राथमिक योजनाओं की घोषणा और विपक्ष की रणनीति पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिलहाल इतना तय है कि राज्य की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों अपने-अपने मोर्चों पर सक्रिय होकर आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार होते दिखाई दे रहे हैं।

राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव का बिगुल, 18 जून को मतदान; कर्नाटक में शुरू हुई राजनीतिक सरगर्मियां

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर चुनावी हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा की चार सीटों और विधान परिषद (एमएलसी) की सात सीटों के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इन महत्वपूर्ण चुनावों के लिए मतदान 18 जून को विधानसभा परिसर स्थित विधान सौधा में होगा, जहां राज्य के विधायक अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। यह चुनाव केवल रिक्त होने वाली सीटों को भरने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा-जेडी(एस) गठबंधन की राजनीतिक ताकत का भी परीक्षण माने जा रहे हैं। विधानसभा में वर्तमान संख्या बल को देखते हुए कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन और संभावित राजनीतिक रणनीतियों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

राज्यसभा की चार सीटें क्यों हो रही हैं रिक्त?

राज्यसभा की जिन चार सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता Iravva Kadadi और Narayana Koragappa के साथ कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge तथा पूर्व प्रधानमंत्री H. D. Deve Gowda का कार्यकाल 25 जून को समाप्त हो रहा है। इनके सेवानिवृत्त होने के बाद इन सीटों को भरने के लिए निर्वाचन कराया जा रहा है।

राज्यसभा चुनावों को लेकर सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस अपने तीन उम्मीदवार उतारती है या कोई नया राजनीतिक समीकरण सामने आता है। पार्टी के पास विधानसभा में पर्याप्त संख्या बल है, जिससे वह तीन सीटें जीतने की स्थिति में मानी जा रही है।

विधान परिषद की सात सीटों पर भी होगा चुनाव

विधान परिषद की सात सीटों के लिए भी चुनाव कराया जाएगा। इन सीटों पर वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। इनमें कांग्रेस के गोविंद राजू, नसीर अहमद, टिप्पन्नप्पा और बीके हरिप्रसाद शामिल हैं, जबकि भाजपा की ओर से एन. नागराज (एमटीबी), प्रताप सिम्हा नायक और सुनील वाल्यापुर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

विधान परिषद चुनाव भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि इससे विधानसभा में दलों की वास्तविक शक्ति का आकलन होगा और भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों की दिशा तय हो सकती है।

चुनाव कार्यक्रम घोषित

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के तहत पूरी की जाएगी।

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि : 8 जून
- नामांकन पत्रों की जांच : 9 जून
- नाम वापस लेने की अंतिम तिथि : 11 जून
- मतदान : 18 जून
- मतगणना : 18 जून

मतदान और मतगणना एक ही दिन संपन्न होगी, जिससे चुनाव परिणाम उसी दिन स्पष्ट हो जाएंगे।

कांग्रेस को संख्या बल का लाभ

224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी राज्यसभा की चार में से तीन सीटें और विधान परिषद की सात में से पांच सीटें आसानी से जीत सकती है।

हालांकि विपक्षी दल भाजपा और H. D. Kumaraswamy की जेडी(एस) यदि संयुक्त रणनीति अपनाते हैं तो कुछ सीटों पर मुकाबला रोचक हो सकता है। फिलहाल दोनों दलों के बीच उम्मीदवारों को लेकर बातचीत की संभावनाओं पर राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है।

उम्मीदवार चयन पर टिकी निगाहें

चुनाव की घोषणा के साथ ही अब सबसे अधिक चर्चा उम्मीदवारों के चयन को लेकर हो रही है। कांग्रेस के भीतर राज्यसभा के लिए कई वरिष्ठ नेताओं और संगठन से जुड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं भाजपा भी ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है जो विपक्ष को एकजुट रखने में मदद कर सकें।

जेडी(एस) की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि भाजपा और जेडी(एस) संयुक्त उम्मीदवार उतारते हैं तो चुनावी गणित में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

राजनीतिक संदेश भी होगा महत्वपूर्ण

राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के परिणाम केवल सीटों के आंकड़े तक सीमित नहीं रहेंगे। इन्हें आगामी राजनीतिक समीकरणों, विपक्षी एकजुटता और राज्य की सत्ता में कांग्रेस की मजबूती के संकेतक के रूप में भी देखा जाएगा। इसलिए राजनीतिक दल इन चुनावों को प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में ले रहे हैं।

बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित, पंजाब की राजनीति में बढ़ा टकराव

चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। पंजाब पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री Bikram Singh Majithia तथा उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। पुलिस का आरोप है कि मजीठिया और उनके समर्थकों ने अमृतसर के मजीठा थाने में घुसकर हंगामा किया, पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली और हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति को जबरन छुड़ाने की कोशिश की।

मामले ने पंजाब की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। जहां पुलिस इसे कानून-व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला बता रही है, वहीं शिरोमणि अकाली दल इसे राजनीतिक प्रतिशोध और विपक्ष को दबाने की कोशिश करार दे रहा है।

अमृतसर ग्रामीण पुलिस के अनुसार, मामले में कार्रवाई के तहत सोमवार को पुलिस टीम मजीठिया के अमृतसर स्थित आवास पर पहुंची थी। हालांकि, पुलिस को वह वहां नहीं मिले। इसके बाद उनकी तलाश और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जो घटना के सभी पहलुओं की जांच करेगी और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण करेगी।

पुलिस के मुताबिक रविवार को मजीठिया अपने समर्थकों के साथ मजीठा थाने पहुंचे थे। आरोप है कि उनके साथ लगभग 50 से 60 लोग मौजूद थे, जिन्होंने थाने में जबरन प्रवेश किया।

पुलिस का दावा है कि भीड़ ने थाने के विभिन्न कमरों में घुसकर अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया। आरोप यह भी है कि कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की तथा जांच से जुड़े दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कानून और प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती देने जैसा मामला है, इसलिए इसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी राजनीतिक हैसियत के आधार पर छूट नहीं दी जाएगी।

विवाद की जड़ एक व्यक्ति जोबनप्रीत की हिरासत को लेकर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार जोबनप्रीत को कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि मजीठिया और उनके समर्थक उसे छुड़ाने के उद्देश्य से थाने पहुंचे और पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया।

पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एसआईटी करेगी पूरे मामले की जांच

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पंजाब पुलिस ने विशेष जांच दल गठित किया है। एसआईटी घटना से जुड़े सभी वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, पुलिस रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच करेगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

दूसरी ओर, शिरोमणि अकाली दल ने पुलिस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था, वह हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में शिअद का पोलिंग एजेंट था।

पार्टी नेताओं का आरोप है कि उसे कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप पुलिस लॉकअप में रखने के बजाय थाना प्रभारी (एसएचओ) के आवासीय परिसर में रखा गया था, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं।

शिअद का कहना है कि मजीठिया केवल अपने कार्यकर्ता की स्थिति जानने और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए वहां पहुंचे थे। पार्टी ने पूरे मामले को "गढ़ा हुआ" और "राजनीतिक बदले की कार्रवाई" बताया है। पंजाब में सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है। ऐसे में मजीठिया के खिलाफ दर्ज यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामले में ईडी को बड़ी राहत वीना विजयन की याचिका पर हाईकोर्ट ने नहीं दी अंतरिम सुरक्षा

कोच्चि। केरल के बहुचर्चित सीएमआरएल-एक्सालॉजिक वित्तीय लेनदेन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को महत्वपूर्ण कानूनी बढ़त मिली है। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस, उसकी मालिक वीना विजयन और कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) को तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए ईडी की जांच पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी कार्रवाई और जांच आगे बढ़ाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। यह मामला पिछले करीब दो वर्षों से केरल की राजनीति, प्रशासन और कारोबारी जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। वित्तीय लेनदेन, कथित अनियमितताओं और राजनीतिक संबंधों को लेकर उठे सवालों ने इसे राज्य के सबसे चर्चित मामलों में शामिल कर दिया है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का प्रमुख केंद्र बना रहा था।

मामले ने उस समय और अधिक तूल पकड़ लिया जब पिछले सप्ताह ईडी ने व्यापक छापेमारी अभियान चलाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के आवास समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग दस स्थानों पर तलाशी कार्रवाई की। इन छापों के बाद सीएमआरएल और संबंधित पक्षों ने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और अंतरिम राहत की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अंतिम निर्णय आने तक ईडी की आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि उन्हें अनावश्यक नुकसान और कानूनी जटिलताओं का सामना न करना पड़े।

हालांकि उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया कि किसी भी चल रही वैधानिक जांच को शुरुआती स्तर पर रोकना न्यायोचित नहीं होगा। न्यायालय ने माना कि जांच एजेंसी को उपलब्ध तथ्यों और कानूनी अधिकारों के आधार पर अपनी प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिलना चाहिए। इसी आधार पर अदालत ने ईडी की जांच पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह रुख ईडी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एजेंसी को बिना किसी अंतरिम बाधा के दस्तावेजों की जांच, वित्तीय लेनदेन की पड़ताल और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करने की स्वतंत्रता मिल गई है। हालांकि याचिका अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और मामले की विस्तृत सुनवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जांच प्रक्रिया पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

राजनीतिक दृष्टि से भी इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष लंबे समय से इस मामले को लेकर सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के परिवार पर सवाल उठाता रहा है। दूसरी ओर वामपंथी दलों का कहना रहा है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों से किया जा रहा है। ऐसे में उच्च न्यायालय का फैसला दोनों पक्षों के लिए नई बहस का आधार बन सकता है। सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामले का केंद्र कथित वित्तीय लेनदेन और व्यावसायिक समझौतों से जुड़ा है, जिनकी जांच ईडी धन शोधन के संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संबंधित भुगतान और कारोबारी लेनदेन वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप थे या नहीं तथा उनमें किसी प्रकार की अनियमितता या धन शोधन के तत्व मौजूद हैं या नहीं। फिलहाल अदालत के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच प्रक्रिया जारी रहेगी और ईडी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई कर सकेगी। अब सभी की नजरें मामले की आगामी सुनवाई और ईडी की आगे की जांच पर टिकी हैं, क्योंकि इस प्रकरण के निष्कर्ष का असर केवल कानूनी स्तर पर ही नहीं बल्कि केरल की राजनीति पर भी पड़ सकता है।

संपादकीय

पंजाब के संकेत

सही मायने में पंजाब के हालिया स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों के आधार पर अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्णायक निष्कर्ष तो नहीं निकाले जा सकते। हां, लेकिन इन परिणामों से महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत जरूर मिलते हैं। निस्संदेह, लोकतंत्र की इस छोटी इकाई, नगर निकाय चुनावों में राज्य स्तर का व्यापक परिदृश्य तो नहीं उभरता, बल्कि स्थानीय मुद्दे इन चुनावों में निर्णायक भूमिका जरूर निभाते हैं। वैसे पिछले ट्रेंड के आधार पर कहा जा सकता है कि ऐसे चुनावों में राज्य के सत्ताधारी दल को लाभ निश्चित रूप से मिलता है। इसका कारण यह भी है कि प्रभावी व संपन्न लोग सत्तारूढ़ दल के करीब आना चाहते हैं। मतदाता यह मानकर चलते हैं कि विकास निधि और प्रशासनिक सहायता उन क्षेत्रों में सहज व सरलता से पहुंचती है, जहां सत्तारूढ़ दल से जुड़े प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं। इस तथ्य की पुष्टि एक बार फिर से हुई है, जब इन निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही जबकि भाजपा और अकाली दल निर्दलीय उम्मीदवारों से भी पीछे रह गए। वास्तव में इन आंकड़ों को सावधानी से देखना चाहिए। दरअसल, स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान कुल मतदान का प्रतिशत 64 फीसदी रहा, लेकिन नगर निगमों में यह भागीदारी 60 फीसदी रही, जो बड़े शहरों में मतदाता की सुस्ती को दर्शाता है।

सही मायने में स्थानीय निकाय चुनावों में आमतौर पर मतदाताओं की भागीदारी असमान और कम रही है। माना जाता है कि विधानसभा चुनाव में मतदान आमतौर पर अधिक होता है और राजनीतिक मुद्दे व्यापक होते हैं। इसके बावजूद, यह चुनाव निष्कर्ष विपक्ष के लिए चिंताजनक वास्तविकता को दर्शाता है। पंजाब में पांव पसारते नशीली दवाओं के कारोबार, अपराध, कानून व्यवस्था और सरकार की शासन संबंधी नीतियों को लेकर विपक्ष की कड़ी आलोचना के बावजूद, विपक्षी दल जनता की असंतुष्टि को वोटों में तब्दील करने में विफल ही रहे हैं। कांग्रेस गुटबाजी और नेतृत्व की अनिश्चितता से जूझ रही है। वहीं दूसरी ओर शिअद अभी भी बेअदबी विवाद और किसान आंदोलन के राजनीतिक नतीजों से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि, भाजपा राज्य के चुनावी परिदृश्य में अभी भी एक मामूली खिलाड़ी ही साबित हुई है, मगर ऐसा लगता है कि उसने 2027 के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। जट सिख केवल सिंह ढिल्लों की पंजाब भाजपा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति महत्वपूर्ण है। भाजपा ने अपने पारंपरिक शहरी-हिंदू आधार से आगे बढ़ने के प्रयास का संकेत दिया है। निस्संदेह, अभी विधानसभा चुनाव का रास्ता खासा लंबा है। लेकिन फिलहाल, आम आदमी पार्टी ने शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष अभी भी एकजुटता और दिशा की तलाश में लगा हुआ है।

राजनीतिक सरगर्मियों में तेजी लाएंगे चुनाव परिणाम

> विधानसभा चुनाव के पहले के आगामी छह माह पंजाब की राजनीति में बेहद सरगर्मी भरे होंगे। पंजाब नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। नेतृत्व बदलाव के बीच भाजपा भी कुछ जगह जीती।

पंजाब में होली देर से आई है- या फिर जल्दी, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं, जब पाते हैं कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) राज्य में नगर निगम चुनावों में अपनी शानदार जीत का जश्न रंगों, ढोल और मिठाइयों के साथ मना रही है। कांग्रेस काफी पीछे, दूसरे स्थान पर है, और निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन भाजपा और अकाली दल, दोनों से बेहतर रहा है।

चूंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल ढिल्लों को पद संभाले अभी चंद घंटे ही हुए हैं, इसलिए पार्टी के प्रदर्शन पर कोई फ़ैसला सुनाना शायद सही न हो- ढिल्लों के अपने ही इलाके, बरनाला में उसका पूरा सफ़ाया हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि मौजूदा विधानसभा में भाजपा के दो विधायकों में से एक, मुकेरियां से जंगी लाल महाजन ने-जैसा कि मेरी सहयोगी दीपकमल कौर ने लिखा है- खुलकर अकाली दल के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया (वो जीत गया है), जबकि दोनों पार्टियों के बीच कोई गठबंधन नहीं है।

अगर यह चुनाव वाकई इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक पूर्वाभ्यास है, तो यह मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। कुछ लोग कहेंगे कि भाजपा ने नेतृत्व परिवर्तन करने में शायद बहुत ज़्यादा देर कर दी- इतनी देर कि दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू को पंजाब में प्रस्तुत करने का मौका हाथ से निकल गया, और केवल ढिल्लों को कमान संभालने में भी काफ़ी देर हो गई। ज़ाहिर है, इस पद के लिए काफ़ी लॉबिंग हुई, क्योंकि सुनील जाखड़ ने एक साल पहले ही ऐलान कर दिया था कि उन्हें अध्यक्ष पद की ज़िम्मेदारी नहीं निभानी। लेकिन पार्टी को इस बात से ज़रूर राहत महसूस हुई होगी कि उसने मोहाली की एक नगर परिषद, 'नया गांव' में शानदार जीत हासिल की है। यह इलाका चंडीगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ है-और चंडीगढ़ गोल्फ़ क्लब से भी ज़्यादा दूर नहीं, वह जो अपने ऊंचे-नीचे मैदान युक्त गोल्फ कोर्स, बार और पार्किंग के साथ शहर के रईसों की

पसंदीदा जगह है- जबकि 'आप' और कांग्रेस, दोनों ही, सिर्फ़ एक-एक सीट तक सिमटकर रह गई हैं। इस चुनाव ने 'आप' और भाजपा, दोनों के भविष्य की दिशा को कमोबेश साफ़ कर दिया है- 'आप' अपनी ज़मीन बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, जबकि भाजपा राज्य में अपनी पैठ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अब यह साफ़ हो गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ही 'आप' का चेहरा होंगे। दिल्ली का राष्ट्रीय नेतृत्व, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, कमान तो संभालेगा, लेकिन मज़बूती से पर्दे के पीछे रहकर। हर कोई बखूबी वाकिफ है कि पंजाबी लोग सबसे अलग होते हैं, न रुकने वाले बगावती, और अपनी किस्मत की बागडोर खुद अपने हाथों में लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा, भगवंत मान पर उनके अपने ही गढ़ धुरी में लगे सभी आरोप-मसलन, गुटबाज़ी, नशे का मुद्दा, शहर का साफ़-सुथरा न होना-परिणामों पर बेअसर साबित हुए हैं। गत शुक्रवार को हुए धुरी नगर परिषद के चुनावों में 'आप' ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। जहां तक भाजपा की बात है, यह भी उतना ही साफ़ है कि आने वाले चुनावों के प्रबंधन में आरएसएस एक अहम भूमिका निभाएगी। उसके कार्यकर्ता और 'पन्ना प्रमुख' (वह 'प्रमुख' या व्यक्ति जो वोटर लिस्ट के हर पन्ने पर लिखे प्रत्येक वोटर के नाम का हिसाब-किताब रखकर प्रभाव बनाने का काम करता है) पहले से ही ज़मीनी स्तर पर पूरी लगन से काम में जुटे हुए हैं। केवल ढिल्लों का प्रदर्शन कैसा भी रहे-उनकी घोषित सकल संपत्ति 200 से 229 करोड़ रुपये के बीच है, और दिल्ली के वसंत विहार, चंडीगढ़ के सेक्टर 9, दुबई और स्पेन के मारबेला में उनके घर हैं- इस बात का एक साफ़ पैमाना होगा कि आरएसएस ने राज्य में कितनी कड़ी मेहनत झोंकी है।

सवाल यह है कि कांग्रेस आखिर करना क्या चाहती है? इस कॉलम में अक्सर इस पुरानी और बड़ी पार्टी के आपस में लड़ते गुटों की आलोचना की जाती रही है। ये सभी गुट सिर्फ दिल्ली हाईकमान की खुशामद करने की होड़ में लगे रहते हैं- जोकि वास्तव में गत सप्ताह कर्नाटक में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक करवाने में व्यस्त रहा। वहां निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बिना किसी हील-हुज्जत के सत्ता की बागडोर अपने नंबर दो नेता डी.के. शिवकुमार को सौंप दी है।

निश्चित रूप से, पंजाब में भी बहुत से कांग्रेसी उम्मीद भरी नज़रों से दिल्ली हाईकमान से आस लगाएंगे कि वही कुशल दांव-पेच यहां भी दोहराए। असल में, अगर कर्नाटक के अनुभव को पैमाना माना जाए, तो ऐसा लगता है कि पार्टी ने 2021 में खुद को पहुंचाए नुकसान से सबक सीखा है; उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को विधानसभा चुनाव से एक साल से भी कम समय पहले बदल दिया गया था।

दिल्ली स्थित कांग्रेस आलाकमान में अफवाहों का बाज़ार गर्म है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह केरल में मिली सफलता से उत्साह पाकर और तमिलनाडु में अपने हस्तक्षेप से प्रभावित होकर, आने वाले महीनों में पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में (जहां पर 2027 के आखिर में चुनाव होने हैं) और 2028 के आखिर में राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलने को तैयार है। (इसका यह भी मतलब है कि सचिन पायलट को आखिरकार मौका मिल सकता है, क्योंकि डी.के. शिवकुमार की तरह उन्होंने भी कांग्रेस नहीं छोड़ी, जबकि उनके कई साथियों ने ऐसा किया था)।

फिलहाल, बीते शुक्रवार को नगर निगम चुनावों में पार्टी का खराब प्रदर्शन साफ नज़र आया -यहां तक कि अपने प्रदेशाध्यक्ष राजा वडिंग के गढ़ में भी हार गई। जालंधर के सांसद चरणजीत चन्नी ने तो अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार तक नहीं किया। जिस इलाके में प्रताप बाजवा और सुखजिंदर रंधावा का दबदबा है, वहां के मतदाताओं ने कांग्रेस उम्मीदवारों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और इसलिए, जब पार्टी का शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेता दिल्ली में आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए, तो हर किसी के लिए यह साफ था कि अगर पार्टी को अपना वजूद बनाए रखना है, तो उसे कुछ कड़े फैसले लेने होंगे।

अगले छह महीने काफी लंबे और मुश्किल भरे होने की उम्मीद है। एक-एक दिन गिना जाएगा। विधायक पाला बदलेंगे, कुछ अपना चुनाव क्षेत्र बदलेंगे। प्रवर्तन निदेशालय की लंबी परछाई पूरे प्रदेश पर मंडराती रहेगी। 'आप' के मंत्री संजीव अरोड़ा 9 मई से ही ईडी की न्यायिक हिरासत में हैं। पंजाब के प्रभारी कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे को पिछले साल जुलाई में ईडी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में गिरफ्तार किया था, लेकिन इस साल जनवरी में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी। तो, क्या ये नगर निगम चुनाव आने वाले समय का संकेत हैं, या फिर पंजाब की स्थिति शाहरुख खान के डायलॉग जैसी है : 'क्या पंजाब में पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त'?

प्रेरणा

चरित्र की पूंजी सबसे बड़ी संपत्ति

मनुष्य के जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा और शक्ति का अपना महत्व है, किंतु इन सबसे ऊपर यदि कोई चीज़ है तो वह है चरित्र। एक अच्छा चरित्र व्यक्ति को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जहां केवल धन या शक्ति के बल पर पहुंचना संभव नहीं होता। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाले लोगों ने अपने उत्कृष्ट चरित्र, सच्चाई और ईमानदारी के बल पर अमर कीर्ति प्राप्त की। संत ईसप का जीवन भी इसी सत्य का जीवंत प्रमाण है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके बाहरी स्वरूप, सामाजिक स्थिति या आर्थिक संपन्नता से नहीं, बल्कि उसके विचारों और चरित्र से होती है।

ईसप का जन्म एक गुलाम परिवार में हुआ था। उस समय गुलामी एक कठोर सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थी। गुलामों के पास अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता था। वे अपने मालिकों की संपत्ति माने जाते थे और उनका जीवन कठिनाइयों तथा अभावों से भरा होता था। लेकिन ईसप ने इन परिस्थितियों को अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने दिया। बचपन से ही वे सत्यवादी, विनम्र, बुद्धिमान और संस्कारी थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मनुष्य अपने आचरण और विचारों से स्वयं को श्रेष्ठ बना सकता है।

समय के साथ जब ईसप युवा हुए, तब उनके मालिक ने उन्हें अन्य दो गुलामों के साथ बाजार में बेचने का निश्चय किया। उस युग में गुलामों की खरीद-फरोख्त सामान्य बात थी। बाजार में खरीदार गुलामों की ताकत, कार्यक्षमता और उपयोगिता को देखकर उन्हें खरीदते थे। उसी दिन वहां एक प्रसिद्ध दार्शनिक जॉनसन भी आए हुए थे। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो केवल मेहनती ही नहीं बल्कि समझदार और विश्वसनीय भी हो।

जॉनसन ने सबसे पहले एक गुलाम से पूछा, "यदि मैं तुम्हें खरीद लूं तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो?" उसने तुरंत सिर झुकाकर उत्तर दिया, "स्वामी, आप जो आदेश देंगे, मैं वही करूंगा।" फिर उन्होंने दूसरे गुलाम से यही प्रश्न किया। उसने भी कहा, "हम दोनों मिलकर आपका सारा काम कर देंगे।" दोनों के उत्तर सामान्य थे। वे अपने मालिक को प्रभावित करने के लिए वही कह रहे थे जो अधिकांश लोग ऐसी स्थिति में कहते।

अब बारी ईसप की थी। जॉनसन ने उनकी ओर देखकर वही प्रश्न दोहराया। ईसप ने मुस्कुराते हुए अत्यंत सहजता से उत्तर दिया, "जब सारा काम यह दोनों ही कर देंगे तो मेरे लिए करने को बचेगा क्या?" यह उत्तर सुनकर वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनके शब्दों में हास्य भी था और बुद्धिमत्ता भी। उन्होंने स्वयं को बड़ा दिखाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। जॉनसन को यह उत्तर बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें एक स्वतंत्र सोच और आत्मविश्वास झलक रहा था।

जॉनसन ने महसूस किया कि यह युवक साधारण नहीं है। उन्होंने आगे पूछा, "यदि मैं तुम्हें खरीद लूं तो क्या तुम पूरी ईमानदारी से काम करोगे?" यह ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर किसी भी गुलाम के भविष्य को प्रभावित कर सकता था। अधिकांश लोग मालिक को प्रसन्न करने के लिए बड़े-बड़े वादे कर देते, लेकिन ईसप ने सत्य का मार्ग चुना। उन्होंने शांत स्वर में कहा, "महोदय, आप मुझे खरीदें या न खरीदें, मेरी ईमानदारी हमेशा मेरे साथ रहेगी।"

यह उत्तर सुनते ही जॉनसन गहराई से प्रभावित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह व्यक्ति केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि सिद्धांतों वाला भी है। उसकी ईमानदारी किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं थी। वह केवल लाभ प्राप्त करने के लिए सत्य की बातें नहीं कर रहा था, बल्कि सत्य उसके जीवन का स्वभाव बन चुका था। यही कारण था कि जॉनसन ने बिना किसी संकोच के ईसप को खरीद लिया।

ईसप के जीवन का यह छोटा-सा प्रसंग बहुत बड़ी शिक्षा देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए चतुराई, प्रभाव या अवसरों की आवश्यकता होती है। यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन स्थायी सफलता और सम्मान केवल अच्छे चरित्र से ही प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति के भीतर ईमानदारी नहीं है, तो उसकी उपलब्धियां भी अधिक समय तक टिक नहीं पातीं। दूसरी ओर, चरित्रवान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी लोगों का विश्वास जीत लेता है। ईसप ने अपने जीवन में कभी भी सत्य और नैतिकता का साथ नहीं छोड़ा। उनकी बुद्धिमत्ता और सच्चाई ने उन्हें धीरे-धीरे समाज में विशेष पहचान दिलाई। उन्होंने अनेक प्रेरणादायक कथाओं की रचना की, जो आज भी विश्वभर में पढ़ी जाती हैं। उनकी कहानियों में पशु-पक्षियों और साधारण घटनाओं के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य प्रस्तुत किए गए हैं। इन कथाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा देना भी है। यही कारण है कि सदियों बीत जाने के बाद भी ईसप का नाम आदर के साथ लिया जाता है।

उनका जीवन यह भी बताता है कि जन्म से कोई महान नहीं होता। महानता कर्मों से प्राप्त होती है। एक गुलाम परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता, सत्यनिष्ठा और परिश्रम के बल पर विश्वविख्यात साहित्यकार और संत बन सकता है, तो इसका अर्थ है कि सफलता का मार्ग सभी के लिए खुला है। आवश्यकता केवल सही दिशा में प्रयास करने और अपने चरित्र को मजबूत बनाने की है। आज के आधुनिक युग में जब प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, तब ईसप की कहानी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार लोग त्वरित लाभ के लिए झूठ, छल और बेईमानी का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वे जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इतिहास और अनुभव दोनों यह बताते हैं कि ऐसे लाभ अस्थायी होते हैं। अंततः वही व्यक्ति सम्मान और विश्वास अर्जित करता है जो सच्चाई का साथ देता है। ईमानदारी एक ऐसी शक्ति है जो धीरे-धीरे व्यक्ति के चारों ओर विश्वास का वातावरण निर्मित करती है। जब लोग किसी पर भरोसा करने लगते हैं, तो उसके लिए सफलता के नए द्वार खुल जाते हैं। विश्वास खरीदकर नहीं पाया जा सकता, बल्कि उसे अच्छे आचरण से अर्जित करना पड़ता है। ईसप ने यही किया। उन्होंने अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाया और उसी के बल पर अमर हो गए। संत ईसप का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, हमें अपने मूल्यों का त्याग नहीं करना चाहिए।

कमजोर मानसून तो महंगाई का लगेगा तड़का, अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित

मौसम विभाग द्वारा 29 मई को जून से सितंबर मानसून के दौरान 10 प्रतिशत कम बरसात का पूर्वानुमान बेहद चिंताजनक का कारण बन गया है। इससे पहले जारी पूर्वानुमान में 8 प्रतिशत कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई थी। लगभग दस साल बाद देश में कमजोर मानसून के हालात रहने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के लिए यह इसलिए और भी अधिक चिंतनीय हो जाता है कि एक और अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर के आसार नहीं दिख रहे हैं और इसके कारण भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश कच्चे तेल और गैस की समस्या से दो चार हो रहे हैं और इसका सीधा असर महंगाई बढ़ना हो रहा है। दूसरी और अब अलनीनों के प्रभाव से इस साल कमजोर मानसून के कारण 10 प्रतिशत कम बरसात होने से हालात और भी गंभीर होने की संभावना बनती जा रही है। करीब दस साल बाद ऐसे हालात बनने जा रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तर पूर्व को छोड़कर समूचे देश में कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को इसलिए भी नहीं नकारा जा सकता है कि पिछले सालों में भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान लगभग सटीक रहने लगे हैं। मजे की बात यह है कि इस साल गर्मी भी भीषण पड़ रही है और पिछले एक माह में ही जलाशयों में उपलब्ध पानी में तेजी से कमी आई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश के प्रमुख 166 जलाशयों में कुल भराव क्षमता का 24 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है और तेजी से पानी कम होता जा रहा है। दक्षिण भारत के हालात अधिक गंभीर है और वहां लगभग 17 प्रतिशत ही पानी रह गया है। उत्तरी भारत के जलाशयों में 26 तो पश्चिमी भारत के जलाशयों में 28 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है। मानसून भी तय समय से बिलंबित हो रहा है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था मानसूनी बरसात पर बहुत कुछ निर्भर करती है। देश में मानसून सीजन में 87 सेमी बरसात होती है। पूर्वानुमानों को माने तो 2018 में 91 प्रतिशत बरसात हुई थी उसके बाद के सालों में मानसून लगभग अच्छा ही रहा है। पिछले सालों में मानसून की स्थिति देखें तो 2023 में मानसून अवश्य कमजोर रहा है अन्यथा देश में मानसूनी वर्षा 100 प्रतिशत के आसापास व इससे अधिक ही रही है। कमजोर मानसून के कारण भूजल स्तर में गिरावट, अधिक पानी पर निर्भर धान, तिलहन और दलहन की फसल प्रभावित होगी और इस कारण से खाद्य महंगाई बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इससे आम आदमी की थाली पर असर पड़ेगा और सब्जी, दाल और अनाज सभी के भाव बढ़ने का असर दिखाई देगा। इसी तरह से देश के अनेक हिस्सों में पीने के पानी की दिक्कत आम है। बांधों में तेजी से पानी की कमी और मानसून कमजोर रहने से पानी की कम आवक रहती है तो निश्चित रुप से सिंचाई व पेयजल दोनों के लिए पानी की दिक्कत होगी। जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन पर असर होगा तो कुल मिलाकर अर्थ व्यवस्था को प्रभावित होने से कोई नहीं रोक सकता।

दरअसल देश में एक समय था जब सूखा आम होता था और व्यापक स्तर पर अकाल राहत कार्य संचालित होते थे। हांलाकि देश के हालातों में काफी सुधार हुआ है और अकाल को तो लगभग भूल ही चुके हैं। पर सवाल वहीं का वहीं है कि जल संचयन के जो प्रयास होने चाहिए थे और उनका जिस तरह का प्रभाव पड़ना चाहिए था वह अभी तक सामने नहीं आया है। सरकार के सामने कमजोर मानसून के हालात से निपटने की बड़ी चुनौती आने वाली है। सबसे अधिक तो जल संग्रहण की चुनौती होगी क्योंकि प्राकृतिक जल संग्रहण के रास्ते शहरीकरण की भेंट चढ़ चुके हैं। दीर्घकालीन सोच के साथ ठोस प्रयास नहीं होने से बरसात के पानी का सही तरीके से संग्रहण भी नहीं हो पा रहा है। जितने पानी की साल भर आवश्यकता होती है उससे अधिक बरसाती पानी तो बह जाता है। इसके अलावा पानी का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही बढ़ गए हैं। कम पानी से तैयार होने वाली फसलों की किस्में विकसित करने में हम अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाये हैं। पांच नदियों के प्रदेश पंजाब तक में पानी का संकट होने लगा है। खेती ही नहीं घरेलू जरुरतों में भी पानी का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। टायलेट और कूलरों में पानी की खपत बहुत अधिक बढ़ गई है। जल बचाओ मात्र स्लोगन ही रह गया है और इसका असर दिखाई नहीं देता। इसी तरह से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार तो बहुत किये गये हैं पर उनके निर्माण में जिस तरह की लापरवाही बरती गई है वह किसी से छिपी नहीं हैं। क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कितना सफल रहा है वह सामने हैं। बाहरमासी नदी नालें तो अब कल्पना की बात हो गए हैं बल्कि बरसाती नदियां भी बरसात में एकाध बार ही पूरे वेग से बहती दिखती है। ऐसे में गंभीरता को तो समझा ही जा सकता है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि मानसून हमेशा सामान्य ही रहेगा यह सोचना अपने आप में गलत होगा। जिस तरह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जंगल घटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं वह किसी और की देन नहीं हमारे कारण ही हो रहा है। हालात यह हो गए हैं कि सर्दी में सर्दी नहीं और गर्मी में गर्मी को तरसने लगे हैं। यहां तक कि इस बार तो बसंत की प्रतीक्षा ही करते रह गए हैं। जनवरी फरवरी में सर्दी तो फिर मार्च अप्रेल में गर्मी का असर देखा गया। बसंत कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। कहने का अर्थ है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम सामने हैं। प्राकृतिक विपदाएं अधिक होने लगी है। ग्लेसियरों में तेजी से बर्फ पिघल रही है, समयपर बर्फवारी कम होने लगी है। बेमौसम आंधी ओलावृष्टि आम होती जा रही है। खैर यह विषयांतर होगा पर कहीं ना कहीं मानसून को लेकर दीर्घकालीन रणनीति बनानी ही होगी ताकि कमजोर मानसून का जनजीवन और अर्थ व्यवस्था पर व्यापक असर नहीं पड़े। सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे।

अभियान

जब उपवास बन जाता है आत्मबल का उत्सव

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कुछ ऐसे व्रत और पर्व हैं जो केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। संकष्टी चतुर्थी ऐसा ही एक विशिष्ट व्रत है, जो भगवान गणेश की उपासना के माध्यम से व्यक्ति को आत्मसंयम, धैर्य, विवेक और मानसिक दृढ़ता का संदेश देता है। यह व्रत केवल किसी मनोकामना की पूर्ति या संकटों से मुक्ति की कामना के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह मनुष्य को अपने भीतर झांकने, स्वयं को समझने और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर भी प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में इसे एक ऐसे आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखा गया है जो व्यक्ति को बाहरी उपलब्धियों के साथ-साथ आंतरिक संतुलन प्राप्त करने की दिशा में भी प्रेरित करता है।

भगवान गणेश को हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाता है। वे ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाती है। यह परंपरा केवल धार्मिक विश्वास का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक संदेश भी निहित है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए सबसे पहले बुद्धि, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, और गणेश जी इन्हीं गुणों के प्रतीक हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत व्यक्ति को इन्हीं गुणों को अपने जीवन में विकसित करने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि यह व्रत सदियों से भारतीय जनमानस में विशेष श्रद्धा और सम्मान का विषय बना हुआ है। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला यह व्रत भारतीय पंचांग की एक नियमित आध्यात्मिक परंपरा है। वर्ष भर में आने वाली प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का अपना विशिष्ट महत्व माना गया है। जब यह तिथि मंगलवार को पड़ती है, तब इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जिसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। लाखों श्रद्धालु इस दिन उपवास रखकर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि की कामना करते हैं। किंतु यदि इस व्रत के वास्तविक स्वरूप को समझा जाए तो यह केवल मांगने का नहीं, बल्कि स्वयं को गढ़ने का पर्व है। भारतीय ऋषियों और मनीषियों ने सदैव यह माना कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। मन की चंचलता, इच्छाओं की अधिकता, क्रोध, लोभ और अहंकार मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देते हैं। उपवास इन्हीं प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाने का एक साधन माना गया है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत इसी आत्मनियंत्रण की साधना है। जब व्यक्ति पूरे दिन भोजन, स्वाद और भौतिक सुविधाओं से दूरी बनाकर भगवान के ध्यान में समय बिताता है, तब उसका मन धीरे-धीरे स्थिर होने लगता है। वह अपने भीतर ऐसी शांति का अनुभव करता है जो सामान्य दिनों में संभव नहीं हो पाती।

संकष्टी चतुर्थी की पूजा-विधि भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और भगवान गणेश के समक्ष व्रत का संकल्प लेते हैं। पूजा में दूर्वा, लाल पुष्प, चंदन, धूप, दीप, फल तथा मोदक अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि दूर्वा और मोदक गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं। किंतु इन प्रतीकों के पीछे भी एक संदेश छिपा हुआ है। दूर्वा साधारणता और विनम्रता का प्रतीक है, जबकि मोदक ज्ञान और आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। जब भक्त इन्हें भगवान को अर्पित करता है, तो वह प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर की विनम्रता और ज्ञान की आकांक्षा को भी समर्पित करता है। इस व्रत में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। दिनभर का उपवास चंद्रमा के उदय होने तक रखा जाता है और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। भारतीय ज्योतिष और दर्शन में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। मनुष्य का मन भी चंद्रमा की तरह घटता-बढ़ता रहता है। कभी वह प्रसन्न होता है तो कभी उदास, कभी उत्साहित तो कभी चिंतित। चंद्र दर्शन का तात्पर्य केवल आकाश में चंद्रमा को देखना नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिति को समझना भी है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि मन को संतुलित रखना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी कथाएं भारतीय धार्मिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवताओं और मनुष्यों के सामने जब अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गईं, तब उन्होंने भगवान गणेश की आराधना की। गणेश जी ने प्रसन्न होकर उनके जीवन से बाधाओं को दूर किया और उन्हें सफलता का मार्ग दिखाया। इस कथा का वास्तविक संदेश यह है कि जब मनुष्य धैर्य, श्रद्धा और विवेक के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करता है, तब समाधान अवश्य प्राप्त होता है।

एक अन्य कथा चंद्रमा और भगवान गणेश से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि चंद्रमा ने गणेश जी के स्वरूप का उपहास किया था, जिसके कारण उसे श्राप मिला। बाद में जब उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की उपासना की, तब उसे क्षमा प्राप्त हुई। यह कथा केवल धार्मिक आख्यान नहीं है, बल्कि मनुष्य को अहंकार के परिणामों से सावधान करने वाली शिक्षा भी है। जीवन में सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना उतना ही आवश्यक है जितना कठिन समय में धैर्य बनाए रखना। आधुनिक जीवन के संदर्भ में देखा जाए तो संकष्टी चतुर्थी का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। आज का मनुष्य तकनीकी रूप से अत्यधिक विकसित है, लेकिन मानसिक रूप से पहले की तुलना में अधिक तनावग्रस्त दिखाई देता है। निरंतर प्रतिस्पर्धा, आर्थिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और डिजिटल जीवनशैली ने मन को अशांत बना दिया है। ऐसे समय में संकष्टी चतुर्थी का व्रत एक प्रकार से आत्मविश्राम का अवसर बनकर सामने आता है। यह व्यक्ति को कुछ समय के लिए मोबाइल, मनोरंजन, उपभोग और भागदौड़ से दूर होकर स्वयं के साथ समय बिताने का अवसर देता है। बहुत से लोग आज संकष्टी चतुर्थी को आध्यात्मिक अनुशासन के साथ-साथ एक सकारात्मक जीवनशैली अभ्यास के रूप में भी देखने लगे हैं। दिनभर का नियंत्रित उपवास शरीर को विश्राम देता है। ध्यान और जप मन को शांत करते हैं। पूजा-अर्चना सकारात्मक सोच विकसित करती है। आत्मचिंतन व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानने में सहायता करता है। इस प्रकार यह व्रत शरीर, मन और आत्मा के बीच एक सुंदर संतुलन स्थापित करता है।

भगवान गणेश का स्वरूप भी जीवन प्रबंधन का अद्भुत पाठ पढ़ाता है। उनका विशाल मस्तक हमें व्यापक सोच रखने की प्रेरणा देता है। बड़े कान यह सिखाते हैं कि सुनना सीखना चाहिए। छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती हैं। लंबी सूंड अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है, जबकि उनका विशाल उदर जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने की कला का प्रतिनिधित्व करता है। उनका वाहन मूषक मनुष्य की इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी का उस पर नियंत्रण यह बताता है कि बुद्धि और विवेक के माध्यम से इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संकष्टी चतुर्थी के प्रति विशेष श्रद्धा देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में गणेश भक्ति की परंपरा अत्यंत प्राचीन और लोकप्रिय है। दक्षिण भारत में भी यह व्रत बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत, गुजरात, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यह तथ्य दर्शाता है कि भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है।

संकष्टी चतुर्थी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में आने वाले संकट केवल बाहरी नहीं होते। अनेक बार व्यक्ति अपने भय, असुरक्षाओं, नकारात्मक विचारों और कमजोरियों से भी संघर्ष करता है। इन आंतरिक बाधाओं को दूर किए बिना वास्तविक सफलता संभव नहीं है। भगवान गणेश की उपासना और इस व्रत का अनुशासन व्यक्ति को इन्हीं अदृश्य बाधाओं से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। यह बताता है कि सच्ची विजय बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर प्राप्त नियंत्रण में निहित है। वास्तव में संकष्टी चतुर्थी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मविकास की एक सतत प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को धैर्यवान बनाती है, उसे अनुशासन का महत्व समझाती है और उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार करती है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 : साइबर क्राइम के खिलाफ गुजरात पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक

▸▸ 2289 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, 913 म्यूल अकाउंट के विरुद्ध कार्रवाई, 565 प्राथमिकी दर्ज और 638 की गिरफ्तारी

▸▸ आरबीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से म्यूल अकाउंट के खिलाफ करेगा कार्रवाई, खातों के लेनदेन को जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में साइबर क्राइम के खिलाफ भारत सरकार एक्शन मोड में, गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अभियान को मिली मजबूती

गांधीनगर : गुजरात के नागरिकों को साइबर क्राइम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिकों की पसीने की कमाई साइबर अपराधियों के हाथों में जाने से बचाने और साइबर क्राइम में संलिप्त अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से राज्य पुलिस ने विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन चलाकर निर्णायक कार्रवाई की है।

इस व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में पूरे राज्य में एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया। गुजरात पुलिस के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीसीई) द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन में म्यूल खातों के खिलाफ कार्रवाई करके अलग-अलग मामलों में कुल 2289 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया गया है।

क्या है म्यूल अकाउंट?

म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी धोखाधड़ी से हासिल धन को प्राप्त करने, ट्रांसफर करने और मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) करने के लिए करते हैं। जिस व्यक्ति के पास यह अकाउंट होता है, उसे 'मनी म्यूल' कहा जाता है। साइबर अपराधी इन खातों की मदद से पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। गुजरात पुलिस ने ऐसे म्यूल खातों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही यह ऑपरेशन चलाया है। साइबर अपराधों में म्यूल खातों का इस्तेमाल जानबूझकर या अनजाने में किया जाता है।

ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0

गुजरात पुलिस और साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीसीई) ने वर्ष 2025 में ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 चलाया था। इस ऑपरेशन में सभी पुलिस आयुक्तों, रेंज प्रमुखों, लोकल क्राइम ब्रांच के निरीक्षकों और साइबर पुलिस स्टेशनों को शामिल किया गया। इस ऑपरेशन की दैनिक निगरानी करते हुए मुख्यालय ने प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। गुजरात पुलिस की टीम ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी), समन्वय पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन के जरिए प्राप्त डेटा को एकत्र किया। इस डेटा इंटेलिजेंस के आधार पर सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करके फील्ड पर मिली शिकायतों के लिए एक सपोर्ट टीम बनाई गई। सभी बैंकों को रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए निर्देश देकर उचित तालमेल किया गया। इस प्रकार, डेटा इंटेलिजेंस और उचित तालमेल के माध्यम से, गुजरात पुलिस ने म्यूल अकाउंट की आपराधिक गतिविधि की जड़ों पर प्रहार करके अभूतपूर्व नतीजे हासिल करने में सफलता प्राप्त की है।

ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 की मुख्य उपलब्धियां :-

- ▸▸ कुल एफआईआर : 565
- ▸▸ कुल गिरफ्तारी : 638
- ▸▸ म्यूल अकाउंट पर कार्रवाई : 193
- ▸▸ अपराधों की पहचान : 4052 (गुजरात में 491)
- ▸▸ आर्थिक धोखाधड़ी का मूल्य : 2289 करोड़ रुपए

ऑपरेशन के कारण एटीएम और चेक द्वारा आहरण (विड्रॉल) में देखा गया बदलाव :-

- ▸▸ चेक द्वारा आहरण में 75 फीसदी कमी
- ▸▸ मासिक चेक आहरण 126 करोड़ से घटकर 25 करोड़ रुपए हुआ, जो 80 फीसदी की कमी दिखाता है
- ▸▸ पहली लेयर के म्यूल अकाउंट यानी ऐसे अकाउंट, जहां सबसे पहले पैसे जमा होते हैं, की संख्या में अगस्त से दिसंबर 2025 तक 30 फीसदी की कमी
- ▸▸ सितंबर से दिसंबर 2025 तक एटीएम आहरण में 66 फीसदी की कमी

आरबीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से म्यूल अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करेगा

म्यूल अकाउंट के खिलाफ इस अभियान को और अधिक कार्यकुशल और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मार्गदर्शन में इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन (आईडीपीआईसी) के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के उपयोग से रिस्क स्कोरिंग प्रणाली लागू की जा रही है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक लेनदेन को लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क के रूप में वर्गीकृत किया जेगा, जिससे संदिग्ध अकाउंट की पहचान की जा सके। इस स्कोर के आधार पर विभिन्न बैंक आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। आईडीपीआईसी को इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी दी गी है। संदिग्ध अकाउंट से संबंधित जानकारी को विभिन्न बैंकों के बीच साझा करने के लिए 'म्यूलहंटर डॉट एआई' (mulehunter.ai) नामक रजिस्ट्री भी बनाई गई है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की है और नागरिकों से डिजिटल अरेस्ट जैसे विभिन्न साइबर अपराधों के खिलाफ बिना डरे अधिक जागरूकता के साथ डिजिटल प्रक्रियाएं करने को कहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में भारत में डिजिटल क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति हुई है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या अभी 100 करोड़ से भी अधिक है, जो 11 वर्ष पहले 25 करोड़ थी। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में वृद्धि और संसद से लेकर पंचायतों तक 'भारतनेट' से जुड़ना, डिजिटल इंडिया की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मामले में भी 16 फीसदी की वृद्धि हुई है। भारत नेट परियोजना के तहत 11 वर्ष पहले केवल 546 पंचायतें जुड़ी थीं, लेकिन आज 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इस परियोजना से जुड़ चुकी हैं। इसी प्रकार, यूपीआई ट्रांजेक्शन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के अनुसार साइबर सुरक्षा अब केवल आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहा, अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ गया है। इसलिए, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के आयामों को मजबूती से सुरक्षित करना और डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

अहमदाबाद मंडल का मई 2026 में रिकॉर्ड प्रदर्शन: माल भाड़ा राजस्व 517.34 करोड़ पार,अहमदाबाद मंडल की बड़ी छलांग: माल लदान, राजस्व और यात्री सेवाओं में दर्ज की रिकॉर्ड वृद्धि

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के परिचालन विभाग ने मई 2026 के महीने में माल लदान (फ्रेट लोडिंग), राजस्व सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और यात्री सेवाओं के मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं।

वित्तीय एवं माल लदान (लोडिंग) की मुख्य विशेषताएं

राजस्व में वृद्धिः मंडल ने मई 2026 में 517.34 करोड़ रुपये का माल भाड़ा राजस्व अर्जित किया।

रिकॉर्ड लदानः इस महीने कुल 3.93 मिलियन टन (MT) माल का लदान किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 3.83 मिलियन टन की तुलना में 2.6% की वृद्धि दर्शाता है । इस दौरान प्रतिदिन औसतन 2639.48 वैगनों का लदान किया गया।

प्रमुख वस्तुएं (कमोडिटी): मई 2025 की तुलना में कई प्रमुख वस्तुओं के लदान में भारी उछाल देखा गया, जिसमें नमक (औद्योगिक नमक सहित) में +31.53%, उर्वरक (फर्टिलाइजर) में +13.02% और अन्य वस्तुओं में +22.64% की वृद्धि दर्ज की गई।

गांधीधाम क्षेत्र का नेतृत्वः माल लदान के मामले में गांधीधाम क्षेत्र सबसे आगे रहा, जहां प्रतिदिन औसतन 1936.97 वैगनों का लदान किया गया।

"कच्छ से कश्मीर" बिजनेस पहल

बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (BDU) के

प्रयासों से गांधीधाम क्षेत्र ने लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है । 5 मई 2026 को, मंडल ने "कच्छ-टू-कश्मीर" माल परिवहन पहल के तहत 20 BCN वैगनों में भीमासर (BMSR) से बारी ब्राह्मण (BBMN) और अनंतनाग (ANT) के लिए खाद्य तेल की पहली खेप भेजी गई।

बुनियादी ढांचा विकास और परिचालन क्षमता

नई वाई-कनेक्टिविटी (Y-Connectivity): चांदखेड़ा-गांधीग्राम वाई-कनेक्टिविटी के चालू होने के बाद पहली बार इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ । 29 मई 2026 को ट्रेन संख्या 09257 ने गांधीग्राम (GG) से चांदखेड़ा रोड के बीच पहला सफल संचालन किया गया।

लॉन्ग हॉल और क्रैक ट्रेनें: मंडल ने इस महीने रिकॉर्ड 149 लॉन्ग-हॉल ट्रेनें चलाईं, जो मई 2025 की 28 ट्रेनों की तुलना में 432.14% की भारी वृद्धि है। इसके साथ ही, महीने के दौरान 1720 क्रैक ट्रेनों का भी संचालन किया गया ।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) इंटरचेंज: डीएफसी पॉइंट्स पर ट्रेनों का इंटरचेंज 7.43% बढ़कर औसतन 88.19 ट्रेनें प्रतिदिन हो गया, जो मई 2025 में 82.09 ट्रेनें प्रतिदिन था ।

अवरोधों को हटानाः परिचालन को सुगम बनाने के लिए 4 प्रमुख अवरोधों को स्थाई रूप से समाप्त किया गया । इसमें रोड अंडर ब्रिज (RUB) के माध्यम से राधनपुर-पिपली सेक्शन के बीच लेवल क्रॉसिंग (LC) 101 को हटाना और सनोसरा-नलिया सेक्शन में पुल संख्या 331 और 337 पर गति प्रतिबंधों (SR) में ढील देकर गति 70 किमी प्रति घंटा करना शामिल है ।

यात्री और कोचिंग ट्रेनों की सफलता

समयपालनबद्धता (Punctuality): मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की समयपालनबद्धता में सुधार हुआ है और यह मई 2025 के 91.06% से बढ़कर मई 2026 में 93.12% पर पहुंच गई है।

अतिरिक्त कोच जोड़नाः यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ट्रेनों में 434 अतिरिक्त कोच जोड़े गए।

नई ट्रेनों की शुरुआतः 23 मई 2026 को 19403/19404 भुज-दिल्ली-भुज दैनिक एक्सप्रेस शुरू की गई, जिसकी नियमित सेवा 23 मई 2026 से शुरू हुई।

19559/19560 ओखा-तिरुपति साप्ताहिक एक्सप्रेस की भी शुरुआत इस महीने की गई।

ट्रेनों का विस्तारः ट्रेन संख्या 20485/20486 जोधपुर-साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस का 22 मई 2026 से जैसलमेर (JSM) तक विस्तार किया गया ।

सेवाओं का नियमितीकरणः सुरेंद्रनगर-ध्रांगध्रा डेमू सेवा (ट्रेन संख्या 09259), जो पहले 'ट्रेन ऑन डिमांड' (TOD) के रूप में चल रही थी, उसे 12 मई 2026 से नियमित ट्रेन संख्या 79457 के रूप में बदल दिया गया है।

अहमदाबाद मंडल ने माल एवं यात्री परिवहन, सुरक्षा, अवसंरचना विकास तथा परिचालन दक्षता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पश्चिम रेलवे की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वरनामा – इटोला खंड पर ब्रिज के स्टील गर्डरों को पीएससी स्लैब से प्रतिस्थापित करने का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सूरत–वडोदरा रेलखंड के वरनामा एवं इटोला स्टेशनों के मध्य स्थित ब्रिज संख्या 567 {अप एवं डाउन लाइन) पर स्टील गर्डरों के स्थान पर प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट (PSC) स्लैब लगाने का महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह कार्य नियोजित रखरखाव ब्लॉकों के दौरान अत्यंत सावधानी एवं कुशलता के साथ संपन्न किया गया, जिससे रेल परिचालन पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार तीन स्पैन (प्रत्येक 12.2 मीटर) वाले इस पुल पर पीएससी स्लैब स्थापित करने के लिए 500 टन एवं 450 टन क्षमता वाली दो उच्च क्षमता की क्रेनों को एक साथ अलग-अलग स्पैन पर कार्य हेतु तैनात किया गया। बेहतर समन्वय एवं सुनियोजित कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप समस्त कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किया गया तथा सभी ब्लॉक समय पर बहाल कर दिए गए।

पुराने स्टील गर्डरों के स्थान पर पीएससी स्लैब लगाए जाने से पुल की संरचनात्मक मजबूती एवं स्थायित्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही जंग लगने की समस्या में कमी आएगी, रखरखाव की आवश्यकता घटेगी तथा पुल की सेवा अवधि भी बढ़ेगी। यह उन्नयन रेल परिचालन की सुरक्षा, विश्वसनीयता एवं दक्षता को और सुदृढ़ करेगा।

इन महत्वपूर्ण कार्यों की सफल पूर्णता पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल की सुरक्षित, विश्वसनीय एवं आधुनिक रेल अवसंरचना विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल यात्रियों एवं माल परिवहन सेवाओं को और अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए निरंतर अधोसंरचना उन्नयन एवं अनुरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दे रही है।

काकरापार खाड़ी पर अवैध दबाव से सूरत में बाढ़ का खतरा, कार्रवाई की मांग

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

सूरत शहर से होकर गुजरने वाली काकरा खाड़ी के दोनों किनारों पर निर्माणकर्ताओं द्वारा डाले गए अवैध दबाव के कारण हर साल खाड़ी में बाढ़ आती है। इससे सूरत शहर के लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से सूरत शहर से होकर गुजरने वाली काकरा खाड़ी के दोनों किनारों पर श्याम संगी के टेक्सटाइल कुम्भरिया और सारथी टेक्सटाइल कुम्भरिया के अवैध निर्माण के साथ-साथ लिंबायत जोन और सूडा के अवैध निर्माण के कारण भी हर साल काकरा खाड़ी में बाढ़ आती है।

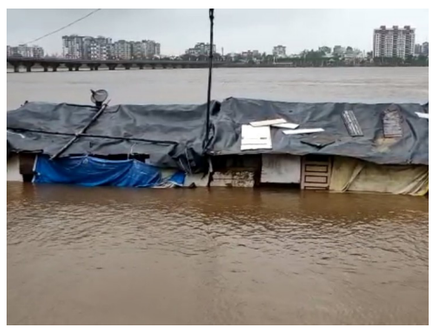

खाड़ी के दोनों किनारों पर स्थित बाजारों के दबाव के कारण जल प्रवाह बाधित होता है। इसके परिणामस्वरूप, लिंबायत, पर्वत पाटिया, पूना और कुम्भरिया जैसे निचले इलाकों में पानी वापस बह जाता है। भारी बारिश होते ही जलभराव के कारण उपरोक्त खाड़ियाँ उफान पर आ जाती हैं। साथ ही, मीठी और कोयली खाड़ियों का जल स्तर भी इस खाड़ी के जल के साथ बढ़ जाता है। इससे पहले, सूरत शहर के सामाजिक कार्यकर्ता छगनलाल डी. मेवाड़ा ने इस संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर की थी। इसके बाद, गुजरात उच्च न्यायालय ने जल निकासी विभाग (SUD) के अधिकारियों को नोटिस भेजा था। लेकिन तत्कालीन SUD अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के नोटिस को भी नजरअंदाज कर दिया। इसके कारण, आम जनता को हर साल खाड़ी की बाढ़ का सामना करना पड़ता है। हर साल उनके घरों और संपत्ति को नुकसान होता है और साथ ही, इन क्षेत्रों के छोटे-बड़े व्यवसायों को भी भारी आर्थिक हानि होती है। इस प्रकार, SUD अधिकारियों की लापरवाही के कारण पूरा सूरत शहर प्रभावित होता है। सूरत शहर के कई लोग व्यापार के लिए इन नालों को पार करके एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी बारिश होते ही ये नाले उफान पर आ जाते हैं।

जिसके कारण आम जनता के साथ-साथ लिंबायत और मीठी खाड़ी क्षेत्रों को भी हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों को नाले के दोनों किनारों पर बने अवैध दबाव को हटाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बाढ़ का पानी आसानी से बह सके और जनता को राहत मिल सके। बाढ़ आने पर ही नगर निगम व्यवस्था सक्रिय होती है और फिर एक साल तक कुंभकर्ण की नींद में सोती रहती है। सूरत नगर निगम के नगर आयुक्त, कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए नाले के दोनों किनारों पर बने दबाव को तुरंत हटाना चाहिए। सूरत नगर निगम के अधिकारी अवैध निर्माणों को हटाने में सक्षम हैं, तो इन बाजारों द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को हटाने से उन्हें कौन रोक रहा है? इससे इस नगर निगम के उच्च अधिकारियों के हाथ तो काले नहीं पड़ गए, है ना?

सूरत के व्यापारी अधूरे बिल्डर प्रोजेक्टों से परेशान हैं, करोड़ों रुपये के फँसे होने के आरोप हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

सूरत की छवि धूमिल हो रही है। ऐसा लगता है कि सूरत की छवि को बिल्डरों द्वारा धूमिल किया जा रहा है क्योंकि शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सहारा दरवाजा, कडोदरा, सरोली, टेक्सटाइल मार्केट, मागोब, पुणे, पर्वत पाटिया, लिंबायत और पूरे शहर में कई बिल्डरों द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाएं लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं और उन पर धूल जम रही है। ये परियोजनाएं ऐसी स्थिति में हैं जहां उनका कोई मालिक नहीं है और इन धूल भरे प्रोजेक्टों में व्यापारियों द्वारा दुकानों, गोदामों या फ्लैटों को बुक करने के लिए बिल्डरों को दी गई अग्रिम राशि फंसी हुई है। न तो बिल्डरों ने इसे वापस किया है और न ही व्यापारियों द्वारा बुक की गई दुकानों, गोदामों या फ्लैटों का कब्जा दिया है।

हमेशा की तरह, बिल्डर खुलेआम उन व्यापारियों को धमकाते हैं जो ऐसे कई धूल भरे प्रोजेक्टों में निवेश किए गए अपने पैसे वापस लेने वाले होते हैं। वे उनसे कहते हैं कि अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए, तो उसमें से 30% से 40% काटकर ही वापस मिलेगा। बाकी पैसा आप जहां चाहें जा सकते हैं। पुलिस के पास जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं या जिसके पास चाहें जा सकते हैं। बिल्डरों द्वारा नियुक्त असामाजिक तत्व खुलेआम व्यापारियों से यह कहते हैं। इस प्रकार, बिल्डर प्रोजेक्ट बुक करने वाले व्यापारियों को आरी की तरह काट रहे हैं। जिस प्रकार आरी लकड़ी को काटती हुई आती-जाती है, उसी प्रकार व्यापारी भी दुकानों, गोदामों या फ्लैटों के लिए दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज नहीं चुकाते और न ही पूरी मूल राशि लौटाते हैं, भले ही वह राशि लंबे समय तक बिल्डर के पास पड़ी रहे। इसके अलावा, वे राशि में से 30% से 40% काटकर वापस करने की बात करते हैं, जिससे ग्राहकों को आर्थिक और मानसिक क्षति होती है, और कभी-कभी शारीरिक क्षति भी होती है।

ऐसे बिल्डर कई कानूनों और नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिनमें आरईआरए का पालन न करना, अनुमति पत्र न होना, योजनाओं को मंजूरी न मिलना, परियोजनाओं को अधूरा छोड़ना, व्यापारियों से अग्रिम राशि लेना और उसे ऐसे पत्र या डायरी में हस्ताक्षर करना जिसे पढ़ा न जा सके, आदि शामिल हैं। इसके अलावा, बिल्डरों द्वारा कई अन्य अवैध कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसके कारण सूरत शहर में बिल्डरों की कई अधूरी परियोजनाएं धूल में पड़ी हैं और उनका कोई भविष्य नहीं है। ये बिल्डर निर्माण व्यवसाय में हैं। व्यापारियों ने इन्हें किसी प्रकार की कोई शपथ नहीं दी है कि यदि आप परियोजना शुरू करेंगे तो हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। यह बिल्डरों का व्यवसाय है। और इस व्यवसाय में कीमतें घटती-बढ़ती रहती हैं। यदि कीमत बढ़ती है, तो बिल्डर परियोजना बुक करने वाले व्यापारियों से तुरंत अतिरिक्त राशि की मांग करते हैं। फिर यदि कीमत घटती है, तो मूल रूप से तय की गई राशि में कोई कमी क्यों नहीं की जाती? इस तरह बिल्डरों द्वारा व्यापारियों को धोखा दिया जा रहा है। योजना की मंजूरी से लेकर लीव लेटर प्राप्त होने तक, यानी 12 से 15 वर्षों तक, जब तक बीयूसी प्राप्त नहीं हो जाता, यदि दलालों के माध्यम से बुकिंग करके परियोजनाओं में निवेश करने वाले व्यापारियों का पैसा पंद्रह दिनों की समय सीमा के भीतर वकीलों के माध्यम से कानूनी रूप से नहीं निकाला जाता है, तो आरईआरए कानून के तहत दलालों और बिल्डरों के खिलाफ अदालत के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जिन व्यापारियों ने खाली नोट या सिर्फ डायरी पर लेन-देन किया है, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साधारण नोट होने पर भी उसे प्रयोगशाला रिपोर्ट के लिए एफएसएल (वित्तीय सेवा प्रदाता) भेजा जाएगा। पुलिस या असामाजिक तत्वों को क्यों न शामिल किया जाए जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और व्यापारियों को न्याय मिलेगा।

भारत-ओमान आर्थिक रिश्तों को मिली नई रफ्तार, सीईपीए लागू होते ही तरजीही शुल्क पर रवाना हुई पहली निर्यात खेप

नई दिल्ली। भारत और ओमान के बीच आर्थिक सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) सोमवार, एक जून 2026 से औपचारिक रूप से लागू हो गया। समझौते के प्रभावी होते ही भारत ने तरजीही शुल्क व्यवस्था के तहत ओमान के लिए अपनी पहली निर्यात खेप रवाना कर दी। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई बंदरगाहों से भेजी गई इस पहली खेप में कृषि उत्पादों के साथ रत्न एवं आभूषण शामिल हैं। इस घटनाक्रम को भारत और ओमान के बीच व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

समझौते के लागू होने के साथ ही भारतीय निर्यातकों को ओमान के बाजार में बेहतर पहुंच मिलने लगेगी। इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय व्यापार को मजबूत आधार मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह समझौता केवल व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निवेश, रोजगार और उद्योगों के विस्तार के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर को भारत की निर्यात नीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सीईपीए के लागू होने से भारतीय निर्यातकों को ओमान के बाजार में शुल्क संबंधी राहत मिलेगी और कई उत्पादों को बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त होगी। इससे भारत के विभिन्न औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को सीधा लाभ पहुंचेगा। उनके अनुसार यह समझौता विशेष रूप से कपड़ा उद्योग, चमड़ा उत्पाद, प्लास्टिक सामग्री, समुद्री उत्पाद, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, खेल सामग्री तथा कृषि क्षेत्र के लिए नए अवसर लेकर आएगा।

गोयल ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और व्यापारिक चुनौतियों के बीच भारत लगातार नए बाजारों की तलाश कर रहा है। ऐसे समय में ओमान के साथ यह समझौता भारतीय उत्पादों को खाड़ी क्षेत्र में मजबूत स्थिति दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और अधिक गहरा होगा तथा व्यापारिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी।

सरकार का मानना है कि सीईपीए का लाभ केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नए निर्यात अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा किसानों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप इकाइयों और आयुष क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी। विशेष रूप से कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को भी मजबूती मिल सकती है।

समझौते के तहत कई उत्पादों को शून्य शुल्क या रियायती शुल्क का लाभ मिलेगा। इससे भारतीय निर्यातकों की लागत कम होगी और वे ओमान के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर अपने उत्पाद उपलब्ध करा सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क में कमी से भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव देश के उत्पादन और रोजगार पर भी पड़ेगा।

व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार खाड़ी क्षेत्र भारतीय निर्यातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार है। ओमान के साथ आर्थिक संबंधों के मजबूत होने से भारत को पश्चिम एशिया में अपनी व्यापारिक उपस्थिति और सशक्त बनाने का अवसर मिलेगा। ओमान लंबे समय से भारत का विश्वसनीय आर्थिक सहयोगी रहा है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध काफी पुराने हैं। अब सीईपीए के माध्यम से इन संबंधों को संस्थागत और व्यापक आधार मिल गया है।

पीयूष गोयल ने इस अवसर पर भारत की व्यापक व्यापारिक रणनीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार वैश्विक स्तर पर नए व्यापार समझौतों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर भी बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ शेष मुद्दों पर चर्चा जारी है और जल्द ही इस दिशा में भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है।

ओमान वर्तमान में खाड़ी क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 11.18 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। यह आंकड़ा दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। अब सीईपीए लागू होने के बाद व्यापारिक गतिविधियों में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के बाद निकट भविष्य में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह दोनों देशों के आर्थिक सहयोग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। व्यापार के विस्तार के साथ-साथ निवेश, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में भी नई साझेदारियां विकसित हो सकती हैं।

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल

ई-निविदा सूचना

मण्डल रेल प्रबंधक (एस एण्ड टी), पश्चिम रेल्वे रतलाम, **निविदा संख्या: SnT_RTM_26_14_SIGNAL दिनांक: 29.05.2026** आमंत्रित करता है। **कार्य का नाम:** देवास-मक्सी खंड में बचे हुये स्टेशन रनायाला जसनिया स्टेशन पर पीआई से ईआई प्रणाली का प्रावधान के संबंध में सिग्नलिंग सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। **कार्य की अनुमानित लागत:** रु. 3,38,57,486.66. **बयाना राशि:** रु. 6,77,200/-. **निविदा बंद करने का समय एवं दिनांक:** 22.06.2026 समय 15:00 बजे तक। **निविदा खुलने का समय एवं दिनांक:** 22.06.2026 समय 15:30 बजे के बाद। **कार्य पूरा करने की अवधि:** 12 माह। **निविदा अनुभाग कार्यालय प्रभारी और बोली खोलने का स्थान:** सीनियर डीएसटीई रतलाम, डीआरएम कार्यालय रतलाम म.प्र.। निविदा सिर्फ अनलाइन ई-निविदा पोर्टल **www.ireps.gov.in** पर देखा व जमा किया जा सकता है।

SPAN/6/1/80

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरत में होगा भव्य आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय

सूरत। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित सूरत दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू हो गई हैं। शहर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सभी विभागों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

राज्य सरकार ने ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के प्रधान सचिव अश्विनी कुमार को इस कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उनके नेतृत्व में प्रशासनिक मशीनरी लगातार कार्यक्रम की तैयारियों की निगरानी कर रही है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, मंच व्यवस्था, अतिथि प्रबंधन और जनसुविधाओं से जुड़े सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसी क्रम में प्रधान सचिव अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में सूरत के इंडोर स्टेडियम परिसर में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम और विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर कार्यक्रम की समाप्ति तक की संपूर्ण कार्ययोजना पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने मुख्य मंच की तैयारियों, स्टेज मैनेजमेंट, विशिष्ट अतिथियों के स्वागत, आमंत्रित मेहमानों के बैठने की व्यवस्था और आम नागरिकों के लिए बनाए जा रहे प्रबंधों की जानकारी प्रस्तुत की। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर लगाए जाने वाले बैनर, होर्डिंग्स, दिशा-निर्देशक संकेतकों तथा सजावट संबंधी

कार्यों की भी समीक्षा की गई।

अश्विनी कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा राज्य और सूरत शहर दोनों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए प्रत्येक विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री की उपस्थिति को देखते हुए पुलिस विभाग और सुरक्षा एजेंसियों को व्यापक सुरक्षा योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा तथा आने-जाने वाले मार्गों की विशेष निगरानी की जाएगी। संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की योजना पर भी विचार किया गया।

यातायात प्रबंधन को लेकर भी प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। कार्यक्रम के दिन बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन, वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग व्यवस्था की विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शहर के सामान्य यातायात पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो।

बैठक में पार्किंग व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण विषय के रूप में लिया गया। कार्यक्रम स्थल के आसपास विभिन्न स्थानों पर वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पार्किंग स्थलों से कार्यक्रम स्थल तक लोगों के सुगम आवागमन के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। प्रशासन का अनुमान है कि कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों की बड़ी भागीदारी रहेगी। सूरत देश के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक शहरों में से एक है, इसलिए उद्योगपतियों, व्यापारिक संगठनों, पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, सामाजिक संस्थाओं तथा शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण रहेगी।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है।

समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर तेजस परमार, नगर आयुक्त एम. नागराजन, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न सरकारी विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की तैयारियों की जानकारी साझा की और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक सहयोग का भरोसा दिया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में तैयारियों की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर अंतिम व्यवस्थाओं को परखने के लिए मॉक ड्रिल और सुरक्षा अभ्यास भी आयोजित किए जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल रहे।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बनेगा, बल्कि सूरत की प्रशासनिक क्षमता और आयोजन प्रबंधन की दक्षता का भी महत्वपूर्ण प्रदर्शन माना जा रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आयोजित यह कार्यक्रम शहर के लिए एक यादगार अवसर साबित होगा।

मेधावी बेटियों ने बढ़ाया प्रदेश का मान, युवाओं को मेहनत और संस्कारों का संदेश दे गए मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोकभवन में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित करते हुए कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का आकलन उसकी बेटियों की उपलब्धियों से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की मेरिट सूची में छात्राओं ने उल्लेखनीय प्रदर्शन कर यह सिद्ध कर दिया है कि अवसर और संसाधन मिलने पर बेटियां हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं। मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

लोकभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए मेधावी छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों और शिक्षकों की उपस्थिति रही। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र, विचार और व्यक्तित्व के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि जब बेटियां शिक्षित होकर आगे बढ़ती हैं तो पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र विकास की नई दिशा प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस बार मेरिट सूची में छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत भी है। उन्होंने कहा कि आज की

बेटियां शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, खेल और रक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं।

अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से सावधान रहने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों का उपयोग आवश्यक है, लेकिन उसका संतुलित और जिम्मेदार इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कई बार भ्रामक और अपुष्ट सूचनाएं तेजी से प्रसारित होती हैं, जिससे युवाओं का ध्यान अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को अपना अधिक समय अध्ययन, ज्ञानार्जन और सकारात्मक गतिविधियों में लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने छात्रों से समाचार पत्र पढ़ने की आदत विकसित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समाचार पत्र और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी विद्यार्थियों के ज्ञान को व्यापक बनाती है तथा उन्हें देश-दुनिया की घटनाओं से अवगत कराती है। उन्होंने कहा कि एक जागरूक विद्यार्थी ही भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति, परंपरा और विरासत से जुड़े रहने का भी आह्वान किया।

योगी आदित्यनाथ ने भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सभ्यता सदियों से शिक्षा, दर्शन, विज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन की अग्रणी रही है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान केवल उसकी आर्थिक या राजनीतिक शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध सांस्कृतिक और ज्ञान परंपरा से भी होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने गौरवशाली इतिहास को जानने और उससे प्रेरणा लेने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भगवान राम और भगवान श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि महान व्यक्तित्वों का निर्माण गुरुजनों के मार्गदर्शन, अनुशासन और निरंतर परिश्रम से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ने सदैव कर्तव्य, साहस और संघर्ष का मार्ग दिखाया है। चुनौतियों से भागना भारतीय परंपरा नहीं रही, बल्कि कठिन परिस्थितियों का सामना कर उन्हें अवसर में बदलना ही हमारी सांस्कृतिक विशेषता रही है।

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नकलविहीन परीक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के साथ-साथ समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने तथा परिणाम घोषित करने की व्यवस्था विकसित की गई है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में केवल परीक्षा प्रणाली ही नहीं, बल्कि विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया गया है। प्रदेश के स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका परिणाम यह है कि आज प्रदेश के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का सफल प्रदर्शन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट के रास्ते से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जीवन में स्थायी सफलता केवल मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी के बल पर ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट का रास्ता भले ही आसान दिखाई दे, लेकिन वह व्यक्ति को लंबे समय तक सफलता नहीं दिला सकता। इसके विपरीत परिश्रम और धैर्य से अर्जित उपलब्धियां स्थायी होती हैं और व्यक्ति को सम्मान दिलाती हैं।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की सफलता में केवल उसका व्यक्तिगत प्रयास ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र का भी योगदान होता है। इसलिए युवाओं को अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से सेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का युवा ही विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं अपनी मेहनत, ज्ञान और संस्कारों के बल पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाएंगे। समारोह में सम्मानित हुए विद्यार्थियों के चेहरे पर उत्साह और गर्व स्पष्ट दिखाई दे रहा था, जबकि अभिभावकों और शिक्षकों ने भी इस अवसर को प्रेरणादायक बताया।

जीएसटी कलेक्शन में लगातार मजबूती, मई में 1.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह; आर्थिक गतिविधियों में तेजी के संकेत

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक और संकेत सामने आया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह ने मई 2026 में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए 1.94 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.2 प्रतिशत अधिक है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.88 लाख करोड़ रुपये था, जबकि इस वर्ष यह बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। लगातार मजबूत कर संग्रह से यह संकेत मिल रहा है कि देश में उपभोग, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियां स्थिर गति से आगे बढ़ रही हैं।

वित्त मंत्रालय और जीएसटी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राजस्व में हुई वृद्धि घरेलू आर्थिक गतिविधियों में मजबूती, बाजार में मांग के विस्तार और आयात पर कर संग्रह बढ़ने का परिणाम है। बीते कुछ महीनों से जीएसटी संग्रह लगातार मजबूत बना हुआ है, जिससे सरकार को विकास योजनाओं और सार्वजनिक निवेश कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त वित्तीय आधार मिल रहा है। मई महीने के दौरान केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के रूप में 37,397 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ, जबकि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) से 45,143 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके अलावा एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के रूप में 51,990 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश के भीतर व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ अंतरराज्यीय और आयात आधारित कारोबार में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी केवल कर वसूली का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का भी महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। जब बाजार में खरीदारी बढ़ती है, उत्पादन गतिविधियां तेज होती हैं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, तब कर संग्रह में स्वाभाविक रूप से वृद्धि देखने को मिलती है। यही कारण है कि आर्थिक विश्लेषक जीएसटी के आंकड़ों को अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण पैमाना मानते हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार मई महीने में कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति में 26.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि बाजार में उपभोक्ता मांग मजबूत बनी हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां विस्तार कर रही हैं। विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं, विनिर्माण क्षेत्र और खुदरा कारोबार में बढ़ती मांग ने कर संग्रह को मजबूती प्रदान की है।

सेवा क्षेत्र ने भी अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मई के दौरान कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति में 22.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन, परिवहन, होटल, वित्तीय सेवाएं, डिजिटल सेवाएं और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण यह वृद्धि संभव हुई है। सेवा क्षेत्र की मजबूती घरेलू खपत और निवेश दोनों के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

मई महीने में आयात पर मिलने वाले कर संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। आयात से प्राप्त आईजीएसटी राजस्व 19.1 प्रतिशत बढ़कर 59,654 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। आर्थिक जानकारों का कहना है कि यह वृद्धि उद्योगों की बढ़ती उत्पादन आवश्यकताओं, कच्चे माल की मांग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों में सुधार का संकेत देती है। आयात आधारित कर संग्रह में तेजी यह भी दर्शाती है कि उद्योगों का उत्पादन चक्र सक्रिय बना हुआ है।

जीएसटी रिफंड के मोर्चे पर भी वृद्धि देखने को मिली है। मई 2026 में कुल 27,281 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.6 प्रतिशत अधिक है। रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आने से निर्यातकों और कारोबारियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में मदद मिली है। उद्योग जगत लंबे समय से समयबद्ध रिफंड व्यवस्था की मांग करता रहा है और हाल के वर्षों में इस दिशा में सुधार देखने को मिला है। रिफंड समायोजन के बाद सरकार का शुद्ध जीएसटी संग्रह लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.3 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि बताती है कि कर संग्रह में स्थिरता बनी हुई है और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार जारी है। गौरतलब है कि अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह ने 2.43 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह रहा है। हालांकि मई में यह आंकड़ा सामान्य रूप से कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी 1.94 लाख करोड़ रुपये का स्तर मजबूत आर्थिक गतिविधियों और बेहतर कर अनुपालन को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग, ई-इनवॉइसिंग व्यवस्था, कर प्रशासन में तकनीकी सुधार और कर चोरी पर नियंत्रण के प्रयासों ने भी जीएसटी संग्रह को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही व्यापारियों में कर अनुपालन की संस्कृति विकसित होने से राजस्व संग्रह की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि आने वाले महीनों में घरेलू मांग, निवेश गतिविधियां और औद्योगिक उत्पादन इसी तरह मजबूत बने रहते हैं तो जीएसटी संग्रह नए रिकॉर्ड बना सकता है। सरकार के लिए यह सकारात्मक संकेत है, क्योंकि मजबूत कर राजस्व से बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण और विकास परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने की क्षमता मजबूत होती है।

कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की मांग को लेकर वकीलों की पहल, डिस्ट्रिक्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

सूरत। शहर में न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक हितैषी बनाने की मांग को लेकर सूरत डिस्ट्रिक्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने सोमवार को जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर और शहर पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें विस्तृत प्रतिनिधित्व पत्र सौंपा तथा विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।

इस दौरान अधिवक्ताओं ने विशेष रूप से अशांत क्षेत्र अधिनियम (डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट) के तहत अनुमति प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना था कि इस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति हस्तांतरण और अन्य संबंधित मामलों में अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया कई बार अत्यधिक समय लेने वाली साबित होती है, जिससे आम नागरिकों के साथ-साथ अधिवक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एसोसिएशन ने प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल बार काउंसिल ऑफ गुजरात की सदस्य प्रीति जोशी ने जिला कलेक्टर के समक्ष कई महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से रखा। उन्होंने लिखित ज्ञापन के साथ मौखिक प्रस्तुति देते हुए बताया कि ई-स्टाम्पिंग से संबंधित आवेदनों के निस्तारण में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बावजूद कई मामलों में आवेदन लंबित रहने से नागरिकों, कारोबारियों और अधिवक्ताओं को अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि ई-स्टाम्पिंग प्रक्रिया के लिए समयसीमा निर्धारित की जाए और लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रीति जोशी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में कई प्रकरण लंबे समय तक लंबित रहते हैं। इसके कारण वृद्धजन समय पर न्याय और राहत प्राप्त नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में देरी का सीधा प्रभाव बुजुर्गों के जीवन और सम्मान पर पड़ता है। इसलिए इन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस संबंध में जिला कलेक्टर को अलग से एक विस्तृत प्रतिनिधित्व पत्र भी सौंपा गया, जिसमें मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की मांग की गई। अधिवक्ताओं का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। दूसरी ओर, शहर पुलिस आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कुछ मामलों में जब अधिवक्ता स्वयं शिकायतकर्ता होते हैं, तब परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं और कई बार दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस-शिकायतें दर्ज होने लगती हैं। ऐसी स्थितियों में निष्पक्ष जांच और संतुलित कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। प्रीति जोशी ने पुलिस विभाग से आग्रह किया कि ऐसे मामलों में संवेदनशील और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि किसी भी पक्ष को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनसे जुड़े मामलों में पारदर्शी तथा न्यायसंगत प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। इससे न केवल न्याय व्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा, बल्कि अनावश्यक विवादों को भी रोका जा सकेगा।

सूरत डिस्ट्रिक्ट लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल अधिवक्ताओं की समस्याओं को उठाना नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक और कानूनी मुद्दों के समाधान में भी रचनात्मक भूमिका निभाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेंगे और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ाने से नागरिकों का भरोसा मजबूत होगा और सरकारी व्यवस्थाओं की कार्यक्षमता में भी सुधार आएगा। उन्होंने प्रशासन से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा लंबित मामलों के निस्तारण के लिए समयबद्ध तंत्र विकसित करने का आग्रह किया।

विदेशी एयरलाइनों को बड़ी राहत, विमान ईंधन में 27% कटौती से उड़ान उद्योग को मिला नया सहारा

नई दिल्ली। वैश्विक विमानन क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। तेल विपणन कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने वाली एयरलाइनों को बड़ी राहत देते हुए विमान ईंधन (एयर टर्बाइन फ्यूल-एटीएफ) की कीमतों में लगभग 27 प्रतिशत की भारी कटौती कर दी है। नई दरें सोमवार रात से प्रभावी हो गई हैं। इस फैसले से विदेशी एयरलाइनों की परिचालन लागत में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, जिससे अंतरराष्ट्रीय विमानन उद्योग को प्रतिस्पर्धी माहौल में बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

नई कीमतों के अनुसार विदेशी एयरलाइनों के लिए एटीएफ का मूल्य 400 डॉलर प्रति किलोलीटर से अधिक घटाकर लगभग 1,100 डॉलर प्रति किलोलीटर कर दिया गया है। इससे पहले मई महीने में एटीएफ की कीमत बढ़ाकर 1,511.86 डॉलर प्रति किलोलीटर कर दी गई थी। लगातार बढ़ती लागत से जूझ रही एयरलाइनों के लिए यह कटौती किसी बड़ी राहत से कम नहीं मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि विमानन क्षेत्र में ईंधन परिचालन लागत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कई एयरलाइनों के कुल खर्च का 35 से 45 प्रतिशत तक हिस्सा ईंधन पर खर्च होता है। ऐसे में एटीएफ की कीमतों में इतनी बड़ी कमी का सीधा प्रभाव एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। इससे कंपनियों को अपने खर्च नियंत्रित करने, मार्ग विस्तार की योजनाओं को आगे बढ़ाने तथा यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने में सहायता मिल सकती है।

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार लगातार अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव, समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ती चुनौतियां तथा कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने वैश्विक ईंधन बाजार को प्रभावित किया है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितताओं का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर लगातार देखा जा रहा है। इसके बावजूद एटीएफ की कीमतों में की गई यह कटौती विमानन कंपनियों के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

विश्लेषकों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय यात्रा की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। पर्यटन, व्यापारिक यात्राओं और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के कारण दुनिया भर में हवाई यातायात तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में ईंधन की कम कीमतें एयरलाइनों को अपनी सेवाओं का विस्तार करने और नए मार्ग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। साथ ही प्रतिस्पर्धा बढ़ने की स्थिति में कुछ एयरलाइंस किरायों में भी राहत दे सकती हैं, जिसका लाभ यात्रियों को मिल सकता है। हालांकि घरेलू विमानन क्षेत्र के लिए इस बार कोई राहत नहीं दी गई है। तेल कंपनियों ने घरेलू उड़ानें संचालित करने वाली एयरलाइनों के लिए एटीएफ की कीमतों को यथावत बनाए रखा है। घरेलू एयरलाइनों के लिए एटीएफ का मूल्य 1,04,927.18 रुपये प्रति किलोलीटर पर स्थिर रखा गया है। यह लगातार दूसरा महीना है जब घरेलू विमानन ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सोलर परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा, ऊर्जा विभाग का अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार; ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति बरामद

अहमदाबाद। गुजरात में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गांधीनगर स्थित ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को पांच लाख रुपये से अधिक की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारी के घरों और अन्य ठिकानों पर की गई तलाशी में करोड़ों रुपये की नकदी, सोने-चांदी के आभूषण तथा संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई ने राज्य के ऊर्जा विभाग और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एसीबी के अनुसार गिरफ्तार अधिकारी अश्विन बी. चौधरी ऊर्जा विभाग में मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय में प्रथम श्रेणी अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उसके खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि वह सोलर परियोजनाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के बदले भारी रिश्वत की मांग करता है। आरोप यह भी है कि कई मामलों में बिना वास्तविक निरीक्षण और तकनीकी जांच किए ही परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की जा रही थी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की निदेशक भारती पंड्या ने बताया कि विभाग को कई सोलर कंपनियों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि अधिकारी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए लाखों रुपये की अवैध मांग करता था। कई मामलों में घटिया गुणवत्ता वाले सोलर पैनल और तकनीकी मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले प्रोजेक्ट भी कथित रूप से रिश्वत के बदले स्वीकृत किए जा रहे थे।

शिकायतों के सत्यापन के बाद एसीबी ने एक विशेष टीम गठित कर निगरानी शुरू की। जांच के दौरान आरोपों के प्राथमिक साक्ष्य मिलने पर अधिकारियों ने जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ने की योजना बनाई। निर्धारित योजना के तहत जब शिकायतकर्ता ने पांच लाख रुपये से अधिक की रिश्वत की राशि सौंपी, उसी दौरान एसीबी की टीम ने छापा मारकर अश्विन चौधरी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

कार्रवाई के दौरान एसीबी अधिकारियों को आरोपी की कार से दो-दो हजार रुपये मूल्यवर्ग के नोटों के दो बंडल भी मिले। प्रारंभिक जांच में इन नोटों के स्रोत और उपयोग को लेकर भी सवाल उठे हैं। इसके बाद जांच एजेंसी ने आरोपी के गांधीनगर और सूरत स्थित आवासों तथा अन्य संभावित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

तलाशी के दौरान जो सामग्री बरामद हुई, उसने जांच अधिकारियों को भी चौंका दिया। एसीबी के अनुसार आरोपी के कब्जे से लगभग एक करोड़ 76 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा करीब 90 लाख रुपये मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण भी मिले हैं। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और संपत्ति का स्रोत क्या है तथा क्या यह कथित रिश्वतखोरी से अर्जित आय का हिस्सा है।

जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार आरोपी अधिकारी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निरीक्षण और स्वीकृति से जुड़ी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आरोप है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों और तकनीकी मानकों की अनदेखी की तथा परियोजनाओं को मंजूरी देने के बदले अवैध धन की मांग की। इससे न केवल सरकारी प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हुई, बल्कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता था।

एसीबी की प्रारंभिक जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार महज एक सप्ताह के भीतर लगभग 100 सोलर परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। सामान्य परिस्थितियों में इतनी बड़ी संख्या में परियोजनाओं का निरीक्षण और तकनीकी मूल्यांकन करना संभव नहीं माना जाता। इसी कारण जांच एजेंसियां अब उन सभी परियोजनाओं की समीक्षा कर रही हैं जिन्हें आरोपी अधिकारी की अनुशंसा या मंजूरी मिली थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला केवल रिश्वतखोरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सौर ऊर्जा क्षेत्र की नियामकीय प्रक्रिया में मौजूद खामियों को भी उजागर करेगा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर निवेश और योजनाएं चला रही है। ऐसे में परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप पूरे क्षेत्र की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं।

एसीबी अब आरोपी के बैंक खातों, निवेश, संपत्ति विवरण, वित्तीय लेनदेन और उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क में अन्य अधिकारी या निजी कंपनियों से जुड़े लोग भी शामिल थे। जांच एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि मामले में आगे और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

गुजरात में सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े इस बड़े भ्रष्टाचार मामले ने प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक ओर राज्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के आरोप यह संकेत देते हैं कि विकास परियोजनाओं की निगरानी और स्वीकृति प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

फिलहाल आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और एसीबी की टीम मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच में जुटी हुई है। जांच के निष्कर्ष आने के बाद इस प्रकरण में और भी बड़ी कार्रवाई होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।